



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]
No. 270]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2008/वैशाख 24, 1930
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 2008/VAISAKHA 24, 1930

गृह मंत्रालय

(सी एस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2008

सा.का.नि. 377(अ).—बंदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध मिस्र गणराज्य की सरकार पर लागू होंगे तथा भारत और मिस्र के बीच हुए करार के पाठ को निम्न प्रकार अधिसूचित करती है अर्थात् :—

“दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा मिस्र अरब गणराज्य की सरकार के बीच करार”

भारत गणराज्य की सरकार तथा मिस्र अरब गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी देश कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से;

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य किसी दंडनीय अपराध करने वाले व्यक्तियों और आजादी से बचने का दण्ड प्राप्त नागरिकों को उनकी नागरिकता के देश में अपनी सजा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :

अनुच्छेद 1

परिभाषा

इस करार के प्रयोजन के लिए :

- (क) "निर्णय" से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के उस निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;
- (ख) "दण्डित व्यक्ति" से तात्पर्य संविदाकारी देशों में तत्समय प्रवृत्त कानून के अंतर्गत स्थापित न्यायालय सहित किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के तहत कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति से है;
- (ग) "प्राप्तकर्ता देश" से तात्पर्य उस देश से है जिसको दंडित व्यक्ति को सजा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जाएगा अथवा अंतरित किया गया हो;
- (घ) "दण्ड" से तात्पर्य किसी दंडनीय अपराध के लिए किसी निर्णय द्वारा आदेशित किसी सीमित या असीमित समयावधि के लिए आजादी से वंचित रखे जाने का उपाय या कोई दंड है ;
- (ङ) "अंतरणकर्ता देश" से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जाएगा या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 2

सामान्य सिद्धांत

1. इस करार के प्रावधानों के अनुसार संविदाकारी देश दण्डित व्यक्ति को अपनी नागरिकता वाले देश में अंतरित करने हेतु एक दूसरे को पूरा सहयोग देंगे ताकि वह अपनी बाकी की सजा वहाँ काट सके।
2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार एक संविदाकार देश के भू-भाग में दंडित व्यक्ति को सजा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई सजा काट सके। इस संबंध में दंडित व्यक्ति इस करार के अंतर्गत अन्तरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
3. अन्तरण का अनुरोध, अन्तरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश द्वारा किया जाए।

अनुच्छेद 3**अन्तरण की शर्तें**

1. इस करार के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जाए:
 - (क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;
 - (ख) दंडित व्यक्ति को मृत्युदण्ड न दिया गया हो;
 - (ग) निर्णय अन्तिम हो;
 - (घ) दंडित व्यक्ति के खिलाफ अन्तरणकर्ता देश में कोई जाँच, विचारण अथवा कोई अन्य कार्यवाही लम्बित न हो;
 - (ङ) अन्तरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय दण्डित व्यक्ति की कम से कम छः माह की सजा शेष रह गई हो अथवा दण्ड मध्यवर्ती हो;
 - (च) यह कि वह कृत्य या चूकें जिनके लिए उस व्यक्ति को अन्तरणकर्ता देश में दंड दिया गया ऐसे हैं जो प्राप्तकर्ता देश में भी अपराध के रूप में दण्डनीय है अथवा यदि उनके भू-भाग में वह अपराध किया जाता तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता।
 - (छ) दंडित व्यक्ति को सैन्य कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है;
 - (ज) प्राप्तकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अन्तरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
 - (झ) अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति अथवा किसी भी संविदाकार देश द्वारा दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी समझे जाने पर संविदाकार देश के कानून के अनुसरण में उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति; और
 - (ञ) अन्तरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।

2. अपवादिक मामलों में, यदि दंडित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दंड की शेष अवधि छः माह से कम हो तो भी अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 4

सूचना भेजने का दायित्व

1. यदि दंडित व्यक्ति ने दंड देने वाले देश को इस करार के तहत अंतरित किए जाने की इच्छा जाहिर की है तो, अन्तरणकर्ता देश निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ज्यों ही व्यवहार्य हो, प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना एवं दस्तावेज भेजेगा, यदि प्राप्तकर्ता देश अथवा अन्तरणकर्ता देश ने पहले ही यह निर्णय नहीं लिया हो कि यह अन्तरण के लिए सहमत नहीं होगा :-

- (क) दंडित व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो;
- (ग) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;
- (घ) दंड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
- (ङ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया;
- (च) दंडित व्यक्ति के पूर्ववृत्त एवं चरित्र के बारे में कोई चिकित्सीय, सामाजिक अथवा कोई अन्य रिपोर्ट, जब उसके आवेदन के निपटान अथवा उसके कारावास के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए यह उपयुक्त हो;
- (छ) कोई अन्य जानकारी जिसके लिए प्राप्तकर्ता देश सभी मामलों में यथापेक्षित यह विनिर्दिष्ट करे कि यह उसके अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को उसके अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके ;
- (ज) अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसरण में उसकी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति का अनुरोध;
- (झ) किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पूरा हो चुका है।

2. इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज तभी भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है:

(क) एक विवरण या दस्तावेज जिसमें यह उल्लेख हो कि दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक है;

(ख) यह मानते हुए कि वे कृत्य अथवा चूकें प्राप्तकर्ता देश के कानून के अंतर्गत एक अपराध है या यदि उनके क्षेत्र में की जातीं तो उन्हें दण्डनीय अपराध माना जाता, ऐसे कृत्यों अथवा चूकों के लिए प्राप्तकर्ता देश के संबंधित कानून की एक प्रति जिसके कारण अंतरणकर्ता देश में सजा सुनाई गई हो;

(ग) दंडित व्यक्ति के अंतरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में दंड की अवधि और प्रवर्तन से संबंधित तथ्य अथवा किसी कानून अथवा विनियम का विवरण और साथ में, यदि लागू हो तो दंडित व्यक्ति पर अनुच्छेद 9 (2) के प्रभाव का विवरण ;

(घ) दंडित व्यक्ति का अंतरण स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की स्वीकृति संबंधी वक्तव्य और दंडित व्यक्ति के शेष बचे दंड का प्रबंध करने के लिए वचन देना;

(ङ) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश जरूरी समझे।

3. किसी भी देश द्वारा अंतरण के अनुरोध पर लिए गए किसी भी निर्णय की सूचना लिखित रूप में दंडित व्यक्ति को दी जा सकती है।

अनुच्छेद 5

अनुरोध एवं उत्तर

1. अंतरण संबंधी अनुरोध लिखित रूप से निर्धारित प्रोफार्मा, यदि कोई हो, में किए जाएंगे तथा ये राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्राप्तकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण के माध्यम से अंतरणकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण को संबोधित होंगे। इन अनुरोधों के उत्तर इन्हीं चैनलों के माध्यमों से दिए जाएंगे।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के प्रयोजनार्थ भारत गणराज्य के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकारी “गृह मंत्रालय” और अरब गणराज्य मिस्र के संबंध में “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग, न्याय मंत्रालय” होगा।

3. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को तत्काल अपने इस निर्णय से अवगत कराएगा कि वह इस अंतरण के अनुरोध से सहमत है अथवा नहीं।
4. कोई भी संविदाकारी देश कोई स्पष्टीकरण दिए बिना दंडित व्यक्ति के अंतरण को मना कर सकता है।

अनुच्छेद 6

सहमति तथा उसका सत्यापन

1. अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 (झ) के अनुसरण में अंतरण की सहमति देने वाला व्यक्ति ऐसी सहमति स्वेच्छापूर्वक और उसके विधिक परिणामों की पूरी जानकारी के साथ दे रहा है। ऐसी सहमति देने की प्रक्रिया अंतरणकर्ता देश के कानून से अधिशासित होगी।
2. अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने का अवसर देगा कि सहमति इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार दी गई है।

अनुच्छेद 7

दंडित व्यक्तियों का सौंपा जाना

1. अंतरणकर्ता देश द्वारा प्राप्तकर्ता देश को अंतरित किए जा रहे व्यक्ति को अंतरणकर्ता तथा प्राप्तकर्ता देशों के मध्य सहमति वाले स्थान पर सौंपा जाएगा। प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश से कैदी को ले जाने तथा अंतरणकर्ता देश के भू-भाग से बाहर दंडित व्यक्ति की अभिरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 8

प्राप्तकर्ता देश पर अंतरण का प्रभाव

1. प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद 9 में दी गई शर्तों के तहत किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश के जरिए, जैसा भी उसके राष्ट्रीय कानून के तहत अपेक्षित हो, दंड का प्रवर्तन जारी रखेगा।
2. इस करार के अनुच्छेद 11 के उपबंधों के अध्याधीन दंड का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा नियंत्रित होगा और केवल वही देश सभी उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

अनुच्छेद 9

दंड का प्रवर्तन

1. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा निर्धारित दंड की कानूनी प्रकृति एवं अवधि के प्रति बाध्य होगा।
2. तथापि, यदि दिया गया दंड अपने स्वरूप अथवा अवधि अथवा दोनों ही दृष्टियों से प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हो अथवा उसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो तो वह देश न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा दंड को अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित सजा अथवा उपाय में परिवर्तित कर सकता है। जहां तक इसके स्वरूप तथा अवधि का संबंध है, सजा अथवा उपाय यथासंभव अंतरणकर्ता देश के फैसले में दी गई सजा के संगत होना चाहिए। तथापि, इससे अंतरणकर्ता देश में दी गई सजा के स्वरूप अथवा अवधि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस करार के अंतर्गत अंतरित किए गए किसी दंडित व्यक्ति पर प्राप्तकर्ता देश में उन कृत्यों अथवा चूकों के लिए मुकद्मा नहीं चलाया जाएगा अथवा उसे दंडित नहीं किया जाएगा जिनके कारण उसे अंतरणकर्ता देश में दंड दिया गया था और उसे उन कृत्यों अथवा चूकों के लिए नजरबंद नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की कोई कार्रवाई इस करार के अनुसार ही की जाएगी।

अनुच्छेद 10

अंतरणकर्ता देश पर दंड पूरा होने का प्रभाव

1. प्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारियों द्वारा दंडित व्यक्ति को नियंत्रण में लिए जाने से, अंतरणकर्ता देश में दंड के प्रवर्तन को स्थगित समझा जाएगा।
2. यदि प्राप्तकर्ता देश का यह मानना है कि दंड का प्रवर्तन पूरा हो गया है तो अंतरणकर्ता देश दंड का अबप्रवर्तन नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 11

माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण

1. जब तक दोनों संविदाकारी देश अन्यथा सहमत न हों, तो अंतरणकर्ता देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दंड का लघुकरण कर सकेगा।

2. केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की समीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।

अनुच्छेद 12

दंड के प्रवर्तन की समाप्ति

1. जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड का प्रवर्तन समाप्त किया जाना हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

अनुच्छेद 13

दंड के प्रवर्तन संबंधी सूचना

1. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा :
 - (क) जब दंड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो;
 - (ख) यदि दंड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है तो ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश द्वारा अपने संगत कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा।
2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 14

अभिवहन

1. यदि कोई भी संविदाकार देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के अभिवहन को सुकर बनाए में सहयोग करेगा। वह देश जिसके भू-भाग पर अंतरण किया जाना है, दंडित व्यक्ति के अभिवहन से मना भी कर सकता है यदि दंडित व्यक्ति उसके अपने राष्ट्रियों में से एक हो। ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकार देश अन्य संविदाकार देश को ऐसे अंतरण के संबंध में पहले से ही एक नोटिस देगा।

अनुच्छेद 15

लागत

1. अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस करार को लागू करने में आने वाले सभी व्यय प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, प्राप्तकर्ता देश अंतरण में होने वाले व्यय की संपूर्ण अथवा आंशिक वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य साधन से कर सकता है।

अनुच्छेद 16

भाषा

1. अनुरोध एवं सहायक दस्तावेजों के साथ प्राप्तकर्ता देश की भाषा अथवा अंग्रेजी में अनूदित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

अनुच्छेद 17

लागू होने का दायरा (टेम्परल)

1. यह करार इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दंड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

अनुच्छेद 18

संशोधन

1. इस करार में किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तन के लिए परस्पर सहमति आवश्यक है, जो दोनों देशों ने अपनी सहमति प्रकट कर दी है, उस समय लागू होंगे जब राजनयिक नोट्स के पारस्परिक आदान प्रदान के माध्यम से इसकी पुष्टि की जाएगी।

अनुच्छेद 19

विवादों का निपटारा

1. इस करार की व्याख्या अथवा इसके अनुप्रयोग संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद का हल राजनयिक माध्यमों से केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाएगा।

अनुच्छेद 20**अंतिम प्रावधान**

1. यह करार, अनुसमर्थन के अधीन होगा तथा उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को अनुसमर्थक दस्तावेजों का पारस्परिक आदान प्रदान किया जाएगा।
2. यह करार उस तारीख से छः माह तक लागू रहेगा जिस तारीख को कोई भी संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को इसे समाप्त करने के बारे में लिखित सूचना देगा।
3. किसी भी परिसमापन के बावजूद यह करार उस दंडित व्यक्ति के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिसे इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।

इस करार के साक्ष्य के रूप में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते इसे मिस्र में दिनांक 08 जनवरी, 2008 को हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषा की दो प्रतियों में तैयार किया गया है। व्याख्या में विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ह/0

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

ह/0

मिस्र अरब गणराज्य की
सरकार की ओर से

[फा. सं. वी -17011/20/2006-पीआर]

निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2008

G.S.R. 377(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of the Arab Republic of Egypt and notifies the text of the agreement entered into between India and the Egypt as follows, namely :—

“Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Arab Republic of Egypt on the Transfer of Sentenced Persons”

The Government of the Republic of India and the Government of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Believing that in order to achieve the above mentioned goals it is necessary to give to persons who committed criminal offences and were sentenced to deprivation of liberty the opportunity to serve their sentence in the State of their Citizenship.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

- (a) “judgement” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) “receiving state” means the State to which the convicted offender may be, or has been, transferred in order to serve his sentence;
- (c) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a judgement for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence;
- (d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in contracting States;
- (e) “transferring State” means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

ARTICLE 2

GENERAL OBLIGATIONS

1. The Contracting States shall mutually undertake to afford each other, according to the provisions of this Agreement, the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons to the State of their Citizenship in order to serve the remaining part of their sentences.
2. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.
3. Transfer may be requested either by the transferring State or the receiving State.

ARTICLE 3

CONDITIONS FOR TRANSFER

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:
 - (a) the person is a national of the receiving State;
 - (b) death penalty has not been imposed on the sentenced person;
 - (c) the judgment is final;
 - (d) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the sentenced person in the transferring state;
 - (e) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or the sentence is indeterminate.
 - (f) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring state are those which are punishable as a crime in the receiving State, or, would constitute a criminal offence if committed on its territory;
 - (g) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;

(h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;

(i) the consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf according to the laws of the Contracting States; and

(j) the transferring and receiving States agree to the transfer.

2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

ARTICLE 4

OBLIGATION TO FURNISH INFORMATION

1. If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State, as soon as practicable after the judgement becomes final, unless either the receiving State or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:-

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person;
- (b) his address, if any, in the receiving State;
- (c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (d) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (e) a certified copy of the judgement and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (f) a medical, social or any other report regarding the antecedents and character of the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
- (g) any other information which the receiving State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him/her under its law;

(h) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring state;

(i) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.

2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

(a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;

(b) a copy of the relevant law of the receiving State constituting the act or omission as the offence, on account of which the sentence has been passed in the transferring State as if such act or omission was an offence under the law of the receiving State or would constitute a criminal offence if committed on its territory;

(c) a statement of fact, or any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence of the sentenced person in the receiving State upon his transfer including, if applicable, a statement of the effect of Article 9 (2) on the sentenced person;

(d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of sentenced person;

(e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

3. The sentenced person may be informed in writing of any decision taken on the request for transfer by either State.

ARTICLE 5

REQUESTS AND REPLIES

1 Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed through the Central Authority of the transferring State

through diplomatic channels to the Central Authority of the receiving State. Replies shall be communicated through the same channels.

2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, the Central Authority shall be, in relation to Republic of India, "the Ministry of Home Affairs", and in relation to the Arab Republic of Egypt it shall be the "Department of International cooperation, Ministry of Justice".

3. The receiving State shall promptly inform the transferring State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

4. Either of the Contracting States may refuse the transfer of sentenced person without the need to provide any explanation.

ARTICLE 6

CONSENT AND ITS VERIFICATION

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph (1) (i) of Article 3 of this agreement does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.

2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 above.

ARTICLE 7

HANDING OVER OF SENTENCED PERSONS

1. The handing over of the transferred person by the transferring State to the receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the transferring and receiving State. The receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the transferring State.

ARTICLE 8

EFFECT OF TRANSFER FOR THE RECEIVING STATE

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under conditions set out in Article 9.
2. Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

ARTICLE 9

ENFORCEMENT OF SENTENCE

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State;
2. If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the laws of the receiving State, or its laws so require, it may, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgement of the transferring State. It shall however not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.
3. A sentenced person transferred under this Agreement shall not be tried or sentenced in the receiving State for the acts or omissions on account of which the sentence was imposed in the transferring State and shall not be detained for those acts or omissions except in accordance with this Agreement.

ARTICLE 10

EFFECT OF COMPLETION OF SENTENCE FOR THE TRANSFERRING STATE

1. The taking into charge of the sentenced person by the authorities of the receiving State shall have the effect of suspending the enforcement of the sentence in the transferring State.
2. The transferring State may no longer enforce the sentence if the receiving State considers enforcement of the sentence to have been completed.

ARTICLE 11

PARDON, AMNESTY OR COMMUTATION

1. Unless both the contracting states otherwise agree, the transferring State alone may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its constitution or other laws.
2. The transferring State alone shall decide on any application for review of the judgement.

ARTICLE 12

TERMINATION OF ENFORCEMENT

1. The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 13

INFORMATION ON ENFORCEMENT OF SENTENCE

1. The receiving State shall notify the transferring State:
 - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
 - (b) if the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed, in such cases the receiving State shall take the necessary action under its relevant law.
2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

ARTICLE 14

TRANSIT

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one of its own nationals. The Contracting State intending to make such a transfer shall give an advance notice to the other Contracting State of such transit.

ARTICLE 15

COSTS

1. Any cost incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, seek to recover all or part of the cost of transfer from the sentenced person or from some other source.

ARTICLE 16

LANGUAGE

1. Requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the language of the receiving State or into English.

ARTICLE 17

TEMPORAL APPLICATION

1. This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after its entry into force.

ARTICLE 18

AMENDMENTS

1. Any amendments or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States shall come into effect when confirmed by an Exchange of Diplomatic notes.

ARTICLE 19

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute regarding the interpretation and application of this Agreement shall be resolved mutually by the Central Authorities through diplomatic channels.

ARTICLE 20

FINAL PROVISIONS

1. This agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged.

2. The present Agreement shall continue to remain in force until six months from the date on which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it.

3. This agreement shall, however, continue to apply to the sentenced persons who have been transferred in conformity with its provisions before the date of its termination.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Egypt on the 8th day of January, 2008, in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English text shall prevail.


**For the Government of
the Republic of India**


**For the Government of
the Arab Republic of Egypt**

[F. No. V-17011/20/2006-PR]
NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.